Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

अगस्त (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- मलखंभ, योगा, तलवारबाजी और पिट्ठू शालेय खेलकूद वार्षिक कैलेंडर में शामिल 3
- इंदौर में 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और वन-वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण 3
- यूनेस्को के 'हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप'में मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा बैठक 4
- वन विहार नेशनल पार्क की डिजाइन में तीसरी बार बदलाव 4
- मध्य प्रदेश ट्रांसको का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण 5
- एमपी टूरिज़्म को प्रतिष्ठित e4m गोल्डन माइक्स अवार्ड 5
- इंदौर के सिरपुर तालाब को मिला रामसर साइट का दर्जा 5
- विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना 'ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना' के अनुबंध पर 6
- भोपाल सहित 5 ज़िलों में खुलेंगे पीपीपी मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय 7
- मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में जीता रजत पदक 8
- भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश देगा 550 बिलियन डॉलर का योगदान 8
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित समारोह में बुनकर तथा शिल्पी सम्मानित 9
- संपूर्ण कायाकल्प अभियान 9
- प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र में डेढ़ हज़ार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव 10
- NueGo ने मध्य प्रदेश में इंटरसिटी बस सेवा शुरू की 10
- मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी 11
- चयनित तीन ज़िलों में 623 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ बाँसरोपण 12
- जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को होम्योपैथी दवाओं से मिला उपचार 12
- मध्य प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित 13
- आज़ादी की 'गुमनाम नायिका' सरस्वती राजामणि पर 10 साल की बेटियों ने लिखी पुस्तक 14
- इंदौर के यशवंत सागर को मिला रामसर साइट का दर्जा 14
- डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 15
- गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ 16
- डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 16
- गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ 17
- डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ 17
- गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ 18
- GIFLIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को मिला WOW अवार्ड एशिया 2022 18
- 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ 19
- ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय 19
- एशिया का पहला कागज़ कारखाना फिर से शुरू 20
- गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी हिन्दी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई 20
- मध्य प्रदेश के दो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित 21
- 'मांडू'बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित 21
- ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 22
- मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास 22
- इंदौर में बना प्रदेश का पहला जी.आई.एस. अति उच्च-दाब सब-स्टेशन 23
- मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 23

नोट :

मध्य प्रदेश

मलखंभ, योगा, तलवारबाजी और पिट्टू शालेय खेलकूद वार्षिक कैलेंडर में शामिल

चर्चा में क्यों ?

31 जुलाई, 2022 को मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने राज्यस्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2022-23 में मलखंभ, योगा, तलवारबाज़ी और पिट्टू जैसे पारंपरिक खेलों को शामिल कर संशोधित कैलेंडर जारी किया।

प्रमुख बिंदु

- लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक और ज़िला शिक्षा अधिकारियों को संशोधित कैलेंडर से संबंधित निर्देश जारी किये हैं।
- स्कूल शिक्षा (स्वतंत्र प्रभार) एवं सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार की पहल पर राज्यस्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2022-23 में इन खेलों को शामिल किया गया है।
- मलखंभ मध्य प्रदेश का 'राजकीय खेल' है। राज्यमंत्री परमार की इस पहल से प्रदेश में स्थानीय परंपरागत खेलों को बढ़ावा मिलेगा।
- गौरतलब है कि पूर्व में 13 जुलाई को राज्यस्तरीय शालेय खेलकूद प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर वर्ष 2022-23 के लिये खेलों की सूची जारी की गई थी।

इंदौर में 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और वन-वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में 2300 करोड़ रुपए लागत की 119 किमी. लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन-वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि प्रदूषण से मुक्ति के लिये वाहनों में ईंधन के गैर-परंपरागत स्रोत का उपयोग किया जाना चाहिये। इसके लिये इलेक्ट्रिक, बायो गैस, बायो डीज़ल, ग्रीन हाईड्रोजन, बायो मीथेनॉल आदि गैर-पारंपरिक स्रोतों से संचालित वाहनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सड़कों और इससे जुड़ी अधो-संरचनाओं का तेज़ी से विकास किया जा रहा है। वर्ष 2014 के बाद अकेले मध्य प्रदेश में ही ढाई लाख करोड़ रुपए लागत के कार्य स्वीकृत, निर्मित तथा प्रगतिरत् हैं। इसे बढ़ाकर वर्ष 2024 तक 4 लाख करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।
- उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर मध्य प्रदेश में सड़क संबंधी विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंज़ूरी देने की घोषणाएँ कीं। इसमें प्रमुख रूप से 20 फ्लाईओवर तथा 14 स्थलों पर रोप-वे संबंधी कार्य शामिल हैं।
- केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के 52 ज़िले नेशनल हाई-वे से जुड़ गए हैं। सड़कों का तेज़ी से विकास हो रहा है। इससे परिवहन सुधार के साथ धार-पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। सड़कों के निर्माण से उद्योग, व्यापार तथा रोज़गार बढ़ेंगे।
- मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में यातायात को सुगम बनाने एवं पर्यटकों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के उद्देश्य से रोप-वे निर्माण योजना शुरू की जाएगी। इस योजना को मूल आधार देने के लिये ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा भारत सरकार की कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड के मध्य एम.ओ.यू साइन किया गया।

नोट :

- रोप-वे निर्माण के लिये मध्य प्रदेश शासन द्वारा रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर उज्जैन, रामराजा मंदिर ओरछा, ग्वालियर किला से फूलबाग, कोकता से नादरा बस स्टैंड भोपाल वाया गोविंदपुरा, गोल जोड़ तिराहा (कोलार रोड) से न्यू मार्केट भोपाल, रहली पाटन मार्ग से टिकीटोरिया माता मंदिर रहली, मांडू प्रवेश द्वार से रूपमती महल, सिद्धवरकूट जैन मंदिर से राजेश्वर आश्रम ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी तट से सेलानी टापू ओंकारेश्वर, रनेहफॉल से केन नदी तट खजुराहो, रायसेन पार्किंग से रायसेन किला, शिव मंदिर पार्किंग से चौरागढ़ शिव मंदिर पचमढ़ी, पातालकोट तामिया तथा अमरकंटक में दूध धारा से कपिल धारा स्थल चयनित किये गए हैं।
- उल्लेखनीय है कि रोप-वे निर्माण से न केवल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तथा पर्यावरण-संरक्षण पर फोकस करते हुए प्रदेश में ट्रांसपोर्ट का विकास किया जा सकेगा, बल्कि इससे न्यूनतम भूमि अधिग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण तथा कार्बन फुटप्रिंट कम करने जैसे लक्ष्यों की भी पूर्ति होगी।

यूनेस्को के 'हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप'में मैनेजमेंट प्लान की समीक्षा बैठक

चर्चा में क्यों ?

1 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव, (पर्यटन एवं संस्कृति) शिव शेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव (नगरीय विकास और आवास) संजय दुबे ने होटल ताज लेकफ्रंट में ओरछा से संबंधित दो प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की।

प्रमुख बिंदु

- इसमें 'यूनेस्को' विश्व धरोहर में ओरछा को सम्मिलित करने हेतु नॉमिनेशन डोजियर बनाने और यूनेस्को के 'हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप' में मैनेजमेंट प्लान के संबंध में प्रेजेंटेशन तथा प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई।
- प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने यूनेस्को और द्रोणा संस्था द्वारा दिये जा रहे सुझाव पर ही योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये। साथ ही ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने के लिये हरसंभव प्रयास और आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही।
- 'द्रोणा' की डायरेक्टर डॉ. शिखा जैन ने ओरछा को यूनस्को विश्व धरोहर में शामिल करने के लिये बनाए जा रहे नॉमिनेशन डोजियर का प्रेजेंटेशन दिया।
- यूनेस्को के कंसल्टेंट निशांत उपाध्याय ने यूनेस्को द्वारा 'हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप' में बनाए जा रहे मैनेजमेंट प्लान और धरातल पर किये गए कार्यों की जानकारी दी।
- यूनेस्को नई दिल्ली की कल्चर सेक्टर की प्रमुख जून्ही हान ने कहा कि ओरछा की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिये गौरव का विषय है।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में ग्वालियर एवं ओरछा का चयन यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप में मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिये किया गया है। इन शहरों का चयन भारत ही नहीं, साउथ एशिया के देशों में यूनेस्को द्वारा प्रथम बार किया गया है।

वन विहार नेशनल पार्क की डिजाइन में तीसरी बार बदलाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वन विभाग के सूत्रों ने बताया कि वन विहार नेशनल पार्क की डिजाइन में तीसरी बार बदलाव किया जा रहा है।

प्रमुख बिंदु

- ध्यातव्य हो कि जनवरी 2021 में मुख्यमंत्री चौहान ने वन विभाग के अधिकारियों को एक बैठक में वन विहार को सिंगापुर जू की तरह विकसित करने के निर्देश दिये थे। इसके बाद ईको पर्यटन बोर्ड के सीईओ एसएस राजपूत ने इसकी ड्राईंग-डिजाइन बनवाई थी।
- वन विहार को सिंगापुर की जू की तर्ज पर बनाया जा रहा था। खासतौर पर गेट नंबर 1 की डिजाइन पर कई तरह के इनोवेशन होने थे। यहाँ पर गिरने वाले झरने के पास सेल्फी पॉइंट, लेपर्ड बाड़े के पास स्कॉई वॉक बनना था। अब सिर्फ गेट नंबर-1 की नई डिजाइन बन रही है, जिसे भीमबेटका की तर्ज पर बनाया जाएगा।
- वन विभाग के सूत्रों का कहना है कि समिति के द्वारा स्वीकृत ड्राईंग-डिजाइन में ईको टूरिज्म के अधिकारियों ने कई तरह की खामियाँ निकालीं। इसके बाद नई डिजाइन बनवाई गई। वन विहार व ईको टूरिज्म के अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बनने से डिजाइन रिजेक्ट कर दी गई।

नोट :

मध्य प्रदेश ट्रांसको का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण

चर्चा में क्यों ?

2 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यू बैंक द्वारा वित्तपोषित प्रोजेक्ट का अंतिम कार्य मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पूरा कर लिया है। इसमें 400 के.वी. आष्टा-उज्जैन डबल सर्किट लाइन ऊर्जीकृत की गई।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा मंत्री तोमर ने बताया कि पूरे देश में गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के सहज ट्रांसमिशन के लिये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिये कुछ राज्यों में से मध्य प्रदेश को भी चुना गया था।
- कुल प्रोजेक्ट 2100 करोड़ रुपए में से 840 करोड़ रुपए का लोन जर्मनी के बैंक के.एफ.डब्ल्यू ने स्वीकृत किया था। इन कार्यों को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरा कर लिया है।
- मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर एम.एम. ढोके ने बताया कि इस स्कीम में प्रदेश में 400 के.वी. के तीन सब-स्टेशन, 220 के.वी. के सात सब-स्टेशन, 400 के.वी. की 5 डबल सर्किट लाइनें, 220 के.वी. की 15 डबल सर्किट लाइनें तथा 132 के.वी. की 26 डबल सर्किट की कुल 2773 सर्किट किमी. अति उच्च दाब लाइनें निर्मित की गईं।
- इस स्कीम से 400 के.वी. की 1890 एम.वी.ए. क्षमता, 220 के.वी. में 2400 एम.वी.ए. क्षमता तथा 132 के.वी. में 498 एम.वी.ए. कुल 4788 एम.वी.ए. अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ट्रांसमिशन में नेटवर्क में जोड़ी गई।
- ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम में मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने सागर, उज्जैन तथा मंदसौर में 400 के.वी. के सब-स्टेशन, सेंधवा, कानवन, जावरा, सैलाना, गुड़गाँव, रतनगढ़ तथा नलखेड़ा में 220 के.वी. के सब-स्टेशन तथा 132 के.वी. के दो अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित कर ऊर्जीकृत किये हैं।

एमपी टूरिज़्म को प्रतिष्ठित e4m गोल्डन माइक्स अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव (पर्यटन और संस्कृति) एवं प्रबंध संचालक (टूरिज़्म बोर्ड) शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि एमपी टूरिज़्म को वेलनेस रेडियो कैंपेन के लिये प्रतिष्ठित e4m गोल्डन माइक्स अवार्ड-2022 मिला है।

प्रमुख बिंदु

- ताज होटल, मुंबई में आयोजित अवार्ड के 10वें संस्करण में उप-संचालक दीपिका राय चौधरी ने पर्यटन विभाग की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- प्रमुख सचिव शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन को रेडियो कैंपेन 'खुशियाँ तेरे पीछे चले' को क्रिएटिव श्रेणी में ब्रॉंज अवार्ड मिला है।
- गौरतलब है कि गोल्डन माइक पुरस्कार एक्सचेंज 4 मीडिया ग्रुप द्वारा दिया जाने वाला प्रमुख रेडियो विज्ञापन पुरस्कार है। यह क्रिएटिविटी, प्रमोशन, इनोवेशन, ब्रॉडकास्टर, रीजनल लैंग्वेज रेडियो सहित श्रेणियों में दिया जाता है।

इंदौर के सिरपुर तालाब को मिला रामसर साइट का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

3 अगस्त, 2022 को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पाँच राज्यों के 10 जल-स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले का सिरपुर तालाब भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब तीन रामसर साइट हो गई हैं। 26 जुलाई, 2022 को शिवपुरी ज़िले की माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला था, जबकि भोपाल की बड़ी झील (बड़ा तालाब/भोज ताल) पहले से ही रामसर साइट घोषित है।

नोट :

- केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किये गए 10 नए रामसर साइट्स में तमिलनाडु के छह और गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा के एक-एक स्थल शामिल हैं। इनको मिलाकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के रामसर साइट्स की संख्या 64 हो गई हैं। ये आर्द्रभूमियाँ स्थल देश में 12,50,361 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं।
- इससे पहले 26 जुलाई, 2022 को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश मंख पाँच स्थलों को रामसर साइट्स घोषित किया था। इनमें तमिलनाडु के तीन, मिजोरम में एक और मध्य प्रदेश में एक आर्द्रभूमि स्थल शामिल थे। इनको मिलाकर देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई थी।
- उल्लेखनीय है कि झील संरक्षण के संबंध में ईरान के रामसर नगर में वर्ष 1971 में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की वेटलैंड साइट्स की सूची संधारित की जाती है। विश्व में हो रहे जलवायु असंतुलन और परिवर्तन के दौर में रामसर साइट की भूमिका विश्व के पर्यावरण सुधार में अति महत्त्वपूर्ण है।

रामसर स्थलों के रूप में नामित 10 आर्द्रभूमि

राज्य	आर्द्रभूमि का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तमिलनाडु	कूनथनकुलम पक्षी अभयारण्य	72.04
	मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिज़र्व	52671.88
	वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स	19.75
	वेलोड पक्षी अभयारण्य	77.19
	वेदान्थंगल पक्षी अभयारण्य	40.35
	उदयमार्थंदपुरम पक्षी अभयारण्य	43.77
ओडिशा	सतकोसिया गॉर्ज	98196.72
कर्नाटक	रंगनाथिट्टू बी एस	517.70
मध्य प्रदेश	सिरपुर आर्द्रभूमि	161
गोवा	नंदा झील	42.01
	10 आर्द्रभूमि का कुल क्षेत्रफल	**1,51,842.41**
	भारत में 64 रामसर स्थलों का कुल क्षेत्रफल (उपर्युक्त 10 और स्थलों के पदनाम के बाद)	**12,50,361**

विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना 'ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना' के अनुबंध पर

चर्चा में क्यों ?

4 अगस्त, 2022 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में 600 मेगावाट की ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के अनुबंध पर हस्ताक्षर तथा ऊर्जा साक्षरता अभियान की ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में एनएचडीसी लिमिटेड, एएमपी एनर्जी तथा एसजेवीएन लिमिटेड के साथ अनुबंध हस्ताक्षर तथा उनका आदान-प्रदान किया गया।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि 2027 तक मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 20 हज़ार मेगावाट होगी। मध्य प्रदेश को 'हार्ट ऑफ इंडिया' के साथ 'लंग्स ऑफ इंडिया' बनाने के मार्ग पर राज्य सरकार अग्रसर है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में वर्तमान में 10 फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं। ओंकारेश्वर परियोजना जल पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना होगी। इसके प्रथम चरण में 278 मेगावाट की क्षमता स्थापित होगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप किसी का भी विस्थापन नहीं होगा।
- यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि जल आधारित परियोजना में बिजली का उत्पादन भूमि आधारित सोलर परियोजना की तुलना में अधिक होता है। पानी की सतह पर सौर पैनल लग जाने से पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। इससे 60 से 70 प्रतिशत तक पानी को बचाया जा सकेगा।
- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि परियोजना से 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन-डाईऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। यह एक करोड़ 52 लाख पेड़ लगाने के बराबर है।
- उन्होंने कहा कि प्रदेश वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा से करने के लिये मिशन मोड में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति-2022 का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है।
- प्रदेश में ग्रीन सिटी के विकास की अवधारणा को भी मूर्तरूप दिया जा रहा है। छतरपुर, मुरैना, आगर, शाजापुर और नीमच ज़िलों में सौर परियोजनाओं पर कार्य जारी है।
- ग्राम स्तर तक सोलर पैनल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी शासकीय कार्यालयों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। चंबल के बीहड़ों की भूमि को सुधार कर क्षेत्र का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबलवार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना जन-भागीदारी से ही किया जा सकता है। ऊर्जा साक्षरता अभियान की ऊर्जा आकलन मार्गदर्शिका का विमोचन भी इसी उद्देश्य से किया गया है। अभियान में स्कूल, कॉलेज के विद्यार्थियों और जन-साधारण को बिजली बचाने के लिये संवेदनशील एवं ज़िम्मेदारीपूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित और प्रशिक्षित करना होगा।
- मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष गिर्राज दंडोतिया ने कहा कि ओंकारेश्वर परियोजना जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच ऊर्जा का सुरक्षित स्रोत है। इससे भूमि की भी बचत होगी, जिसका उपयोग प्रदेश में कृषि तथा अन्य उद्योगों की स्थापना में किया जा सकेगा।

भोपाल सहित 5 ज़िलों में खुलेंगे पीपीपी मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रदेश में पीपीपी मॉडल पर आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने हेतु आयोजित समीक्षा बैठक में प्रथम चरण में प्रदेश के 5 ज़िलों में चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- प्रथम चरण में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट एवं कटनी में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया गया।
- मंत्री सारंग ने निर्देश दिये कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना डीबीएफओटी (डिज़ाइन, बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल पर पीपीपी पार्टनर द्वारा की जाएगी। इसके अंतर्गत निजी निवेशक द्वारा मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उपकरण, बुक्स एवं जर्नल्स आदि का व्यय वहन करना शामिल होगा।
- राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये निजी निवेशक को 99 वर्ष (60 वर्ष + 39 वर्ष) की लीज़ पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त निजी निवेशक को 300 बिस्तरों वाला अस्पताल भवन भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- बैठक में निर्णय लिया गया कि उपलब्ध कराई गई भूमि पर निजी निवेशक द्वारा स्वयं के व्यय से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा तथा उसका संचालन एवं संधारण उसी के द्वारा होगा।
- पीपीपी मॉडल आधारित अस्पतालों में आयुष्मान मरीज़ों के साथ ही आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज़ों को भी नि:शुल्क उपचार मिल सकेगा। वहीं गैर आयुष्मान मरीज़ों को बाज़ार दर पर उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना नीति के अनुसार राज्य सरकार के वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेज को ट्रेनिंग हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर 100 एमबीबीएस सीट के प्रवेश के लिये पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

नोट :

मध्य प्रदेश की पूजा ओझा ने वर्ल्ड पैरा कैनो चैंपियनशिप में जीता रजत पदक

चर्चा में क्यों ?

5 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश की पैरा एथलीट पूजा ओझा ने हैलिफैक्स, कनाडा में आयोजित पैरा कयाकिंग और केनोइंग स्प्रिंट वर्ल्ड चैंपियनशिप में VL1 महिलाओं की 200 मीटर रेस में रजत पदक जीता।

प्रमुख बिंदु

- भिंड की रहने वाली पूजा ने VL1 महिलाओं की 200 मीटर रेस में 1:34:18 के समय के साथ रजत पदक जीता है। हैंबर्ग की खिलाड़ी लिलेमोर कोपर ने 1:29.79 समय के साथ स्वर्ण पदक जीता।
- भारत की ओर से दो खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता के लिये क्वालीफाई किया था। एक पूजा ओझा और दूसरे सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार ने VL1 पुरुषों की 200 मीटर श्रृंखला में पाँचवा स्थान प्राप्त किया। सुरेंद्र ने अपनी दौड़ 1:22.97 समय में पूरी की।
- गौरतलब है कि पूजा ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 6 बार स्वर्ण पदक जीता है और विश्व चैंपियनशिप के लिये क्वालीफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पैराएथलीट हैं। वर्तमान में वह दुनिया के शीर्ष पैरा कैनो खिलाड़ियों में नौवें स्थान पर हैं।

भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश देगा 550 बिलियन डॉलर का योगदान

चर्चा में क्यों ?

7 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के लिये मध्य प्रदेश द्वारा 550 बिलियन डॉलर का योगदान दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2020 में ही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप विकसित कर लिया गया था। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2021-22 में 74 प्रतिशत की विकास दर हासिल की है।
- प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद का 4 प्रतिशत पूंजीगत व्यय कर रहा है और वित्त वर्ष 2022-23 के लिये पूंजीगत व्यय हेतु 48 हज़ार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गेहूँ और धान के स्थान पर कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दाल, रागी, जौ, मोटे अनाज, कोदो-कुटकी, रामतिल, तिल, मसाले, औषधीय फसलें, फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- इस योजना में आईटीसी, पतंजलि, देहात जैसी प्राइवेट कंपनियों से एक लाख 86 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि विविधीकरण में 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से दो प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है।
- मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा देवारण्य योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें तीन वर्षों में 10 हज़ार हेक्टेयर भूमि में औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाएगा। पिछले 5 सालों में प्रदेश में 11 हज़ार हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिशन मोड में बाँस उत्पादन किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश में राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है।
- खेती में आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि फसल बीमा पंजीयन को राज्य के लैंड रिकॉर्ड से जोड़ा गया है, जिससे ओवर और डुप्लीकेट इन्श्योरेंस को रोकने में सफलता मिली है। साथ ही, बीमा भुगतान में उपज आकलन के लिये सैटेलाइट आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी के इन प्रभावी उपयोग से कृषि सेक्टर में लगभग 2500 करोड़ रुपए की बचत संभावित है।

नोट :

- किसानों और राजस्व अमले की सुविधा के लिये ई-गिरदावरी एप्लीकेशन लागू कर दिया गया है। किसानों को अपनी उपज का विक्रय अपने घर से उचित मूल्य पर करने के लिये 'फार्म गेट ऐप'भी विकसित किया गया है। प्रदेश में कृषि यंत्रों में सब्सिडी का भुगतान ई-रूपी वाउचर से करने का निर्णय लिया गया है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2021 के राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे में मध्य प्रदेश बड़ी छलांग लगाकर देश में 5वें स्थान पर पहुँच गया है। प्रदेश में 'एडाप्ट एन आँगनबाड़ी'अभियान से आँगनबाड़ियों के कायाकल्प में जनता को जोड़ने का सफल अभियान चलाया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में सत्र 2022-23 से एम.बी.बी.एस. की पढ़ाई हिन्दी माध्यम में प्रारंभ की जा रही है। साथ ही, प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी.टेक. कार्यक्रम और 6 पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की हिन्दी में पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सुशासन की दिशा में की जा रही पहलों की जानकारी देते हुए बताया कि देश में पहली बार प्रदेश में राज्य सांख्यिकी आयोग का गठन किया गया है, जिसके द्वारा विकासखंड से लेकर राज्य स्तर तक आँकड़ों को एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश में 50 आकांक्षी विकासखंडों का निर्धारण कर उनके विकास का तंत्र विकसित किया गया है। प्रदेश में नई जल नीति और नई सहकारिता नीति का भी निर्माण किया जा रहा है।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित समारोह में बुनकर तथा शिल्पी सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

7 अगस्त, 2022 को हथकरघा शिल्पियों तथा बुनकरों की कला को सम्मानित करने एवं हथकरघा उद्योग को समृद्ध करने हेतु गौहर महल में आयोजित 8वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष-2021 के लिये चयनित बाग प्रिंट शिल्पी रशीदा बी सहित अनेक बुनकरों तथा शिल्पियों को सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख सचिव, कुटीर एवं ग्रामोद्योग स्मिता भारद्वाज तथा आयुक्त सह-प्रबंध संचालक हथकरघा, संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम अनुभा श्रीवास्तव ने समारोह में बुनकरों तथा शिल्पियों को सम्मानित किया।
- समारोह में वर्ष-2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चयनित बाग प्रिंट शिल्पी रशीदा बी को सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि बाग शिल्पकार रशीदा बी का केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये चयन किया है। उन्हें यह पुरस्कार चादर पर बाग प्रिंट की बारीक कारीगरी पर मिलेगा।
- उन्हें धार ज़िले के ग्राम बाग में ठप्पा छपाई कला में महारत हासिल है। इससे पूर्व भी वर्ष 2012 और 2014 में उन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार मिले हैं। वे बाग प्रिंट के दुनिया में मशहूर यूनिस्को पुरस्कार विजेता मास्टर शिल्पकार स्व. अब्दुल कादर खत्री की पत्नी हैं।
- राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर पारंपरिक हथकरघा क्लस्टर चंदेरी में मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला विरासत एवं धरोहरों पर की गई नक्काशी की विशिष्ट हेरीटेज डिज़ाइनों को दर्शाते हुए चंदेरी के बुनकरों द्वारा विकसित की गई साड़ियाँ, जिन पर खजुराहो मंदिर एवं साँची स्तूप डिज़ाइन एवं महेश्वर किले की डिजाइन है और सिल्क एवं ज़री के धागों से विकसित करने वाले बुनकरों को सम्मानित किया गया।
- इनमें खजुराहों मंदिर की डिज़ाइन के लिये कलावती कोली, सांची स्तूप की डिज़ाइन के लिये घनश्याम कोली, महेश्वर किले की डिज़ाइन के लिये मोहम्मद गुफरान अहमद तथा महेश्वर किले की ग्राफ डिज़ाइन के लिये मोहम्मद अब्दुल अमान को सम्मानित किया गया।

संपूर्ण कायाकल्प अभियान

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में स्वास्थ्य विभाग के 'संपूर्ण कायाकल्प अभियान' का शुभारंभ किया और अभियान में 66 करोड़ रुपए की राशि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं के प्रभारियों के खातों में ट्रांसफर की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ज़िला अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित भी किया तथा अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये।
- मुख्यमंत्री ने ज़िला अस्पतालों को स्वास्थ्य सेवाओं का श्रेष्ठ संचालन के लिये कायाकल्प अवार्ड प्रदान किये। इनमें विदिशा ज़िला अस्पताल को 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार, ज़िला अस्पताल देवास को 20 लाख रुपए का द्वितीय पुरस्कार और ज़िला अस्पताल सतना को 10 लाख रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान किया।
- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि कायाकल्प अभियान की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। पहले 65 स्वास्थ्य संस्थाएँ पुरस्कृत हुई थीं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश की 395 स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प अवार्ड दिया जा रहा है।
- उन्होंने कहा कि शासकीय अस्पतालों को अधिक सुविधा संपन्न बनाने के लिये संपूर्ण कायाकल्प अभियान शुरू किया जा रहा है।
- इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) मोहम्मद सुलेमान ने बताया कि संपूर्ण कायाकल्प अभियान के अंतर्गत अधो-संरचना का विकास एवं भवन रख-रखाव, चिकित्सा उपकरण एवं फर्नीचर की उपलब्धता, संस्थाओं में जाँच, सेवाओं एवं दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता, डायलिसिस एवं कैंसर की नई उपचार सेवाओं का विकास, ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज का सुदृढ़ीकरण, विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिये टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार, रोगियों के लिये हितग्राही मूलक सेवाओं का विकास और स्वास्थ्य सेवाओं में जन-भागीदारी को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन औद्योगिक क्षेत्र में डेढ़ हज़ार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

8 अगस्त, 2022 को कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के एमडी विनोद अग्रवाल ने भेंटकर प्रदेश में 1,500 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री चौहान को प्रस्तावित परियोजना की प्रति सौंपते हुए विनोद अग्रवाल ने कंपनी की वर्तमान इकाइयों के क्षमता विस्तार के लिये तैयार परियोजना प्रस्ताव से अवगत करवाया।
- वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड द्वारा प्रदेश में वर्ष 1986 में पहली इकाई लगाई गई थी। वर्तमान में पीथमपुर और बागरोदा में 8 इकाइयाँ संचालित हैं, जिनमें 32,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार प्राप्त हो रहा है।
- मध्य प्रदेश की 110 ऑटो कंपोनेंट इकाइयों द्वारा कंपनी की सभी यूनिट्स में सामग्री की आपूर्ति की जाती है। इकाइयों की वर्तमान क्षमता के विस्तार के लिये नवीन उत्पाद निर्माण प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री चौहान ने कंपनी के एमडी को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य शासन द्वारा कंपनी को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। निर्धारित नीति के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे उद्योग आज की आवश्यकता है और इससे बड़ी संख्या में युवाओं को रोज़गार भी प्राप्त होगा।

NueGo ने मध्य प्रदेश में इंटरसिटी बस सेवा शुरू की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक इंटर-सिटी कोच सेवाएँ NueGo ब्रांड ने भोपाल-इंदौर इलेक्ट्रिक इंटरसिटी बस सेवा मार्ग की अपनी सेवाएँ शुरू कर अपना परिचालन शुरू करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- यह बस सेवा एक सुरक्षित और हरित सवारी सुनिश्चित करते हुए अंतर-शहर यात्रियों के लिये एक सहज बुकिंग अनुभव, बेहतर सवारी गुणवत्ता और केबिन अनुभव प्रदान करेगी।

नोट :

- NueGo सेवाएँ भोपाल-इंदौर रूट पर 349 रुपए प्रति सीट के विशेष उद्घाटन प्रस्ताव पर उपलब्ध होंगी।
- कंपनी की ओर से कहा गया है कि NueGo कोचों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। यह भोपाल-इंदौर के बीच घंटे के आधार पर चलने वाले कोचों के साथ, अंतर-शहर यात्रियों के लिये एंड-टू-एंड सुविधा प्रदान करती है।
- भोपाल में कोच रूट आईएसबीटी, भोपाल रेलवे स्टेशन, लालघाटी, सीहोर से होकर गुज़रेगा, जबकि इंदौर में यह स्टार स्क्वायर, रेडिसन स्क्वायर, विजय नगर और सरवटे बस स्टैंड से होकर गुज़रेगा।
- एक ग्राहककेंद्रित ब्रांड NueGo कोच यांत्रिक और विद्युत निरीक्षण सहित 25 कठोर सुरक्षा जाँच से गुज़रते हैं। हर ट्रिप से पहले कोचों को सैनिटाइज किया जाता है और कोच पायलटों का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है।
- NueGo सर्विसेज लाइव कोच ट्रैकिंग, ड्रॉप पॉइंट जियो-लोकेशन और मॉनिटर इन-कोच सीसीटीवी सर्विलांस प्रदान करती है। ये इलेक्ट्रिक कोच ट्रैफिक की स्थिति में एयर कंडीशनर से सिंगल चार्ज पर 250 किमी. चल सकते हैं। इन कोचों ने सेवाओं के शुरू होने से पहले के महीनों में दो लाख किमी. का रोड ट्रायल पूरा कर लिया है।
- NueGo अपनी विश्वस्तरीय इलेक्ट्रिक कोच सेवाओं के साथ यात्रा का संपूर्ण अनुभव प्रदान करेगा। जल्द ही इस सेवा का विस्तार देश के अन्य शहरों में किया जाएगा।
- ग्रीनसेल मोबिलिटी के निदेशक सतीश मंधाना ने कहा कि NueGo का उद्देश्य अंतर-शहर मार्गों पर ज़ीरो टेलपाइप उत्सर्जन के साथ टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देना है। (टेलपाइप के उत्सर्जन मानक एक आंतरिक दहन इंजन से निकलने वाली निकास गैसों में अनुमत प्रदूषकों की अधिकतम मात्रा को निर्दिष्ट करते हैं।)

मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को मंजूरी

चर्चा में क्यों ?

10 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश महिला वित्त एवं विकास निगम का सुदृढ़ीकरण करते हुए स्थापना व्यय के लिए पृथक बजट लाइन प्रावधानित करने, निगम में मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष का गठन और उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना का अनुमोदन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- 'मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना' में 'राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' एवं 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन', 'मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना' तथा 'मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना' की लाभान्वित महिला हितग्राहियों के बैंकों से स्वीकृत प्रकरणों पर 2% ब्याज अनुदान दिया जायेगा।
- मंत्रि-परिषद ने उपरोक्त योजनाओं से वित्त पोषित महिला उद्यमियों के उत्पाद की विपणन व्यवस्था और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित करने के लिये SRLM/NULM में परियोजना प्रबंधन इकाई एवं निगम में परियोजना प्रकोष्ठ स्थापित करने का अनुमोदन किया।
- निगम द्वारा गठित तेजस्विनी समूहों को आजीविका मिशन फोल्ड में लाने के लिये तेजस्विनी कार्यक्रम में उपलब्ध राशि में से 10 करोड़ रुपए ग्रामीण आजीविका मिशन को देने का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रि-परिषद ने 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना' लागू करने का निर्णय लिया।
  - इस योजना में बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधिक आयु के केयर लीवर्स (आफ्टर केयर) और संबंधियों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन-यापन करने वाले 18 वर्ष तक की आयु के अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता (स्पॉन्सरशिप) दी जायेगी।
  - इस योजना में केयर लीवर्स को इंटर्नशिप के समय 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह अधिकतम एक वर्ष के लिये और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने पर 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिये दिये जाएंगे।
  - साथ ही NEET, JEE या CLAT से पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को आजीविका व्यय के लिये 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह दिये जाएंगे।
  - आफ्टर केयर में शिक्षा अथवा इंटर्नशिप अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये समस्त आर्थिक सहायता निर्धारित समयावधि या 24 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो तक दी जायेगी।

नोट :

- स्पॉन्सरशिप में पात्र बच्चों के वैध संरक्षक के संयुक्त खाते में न्यूनतम एक वर्ष और अधिकतम 18 वर्ष तक 2 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता और 'आयुष्मान योजना' में चिकित्सा सहायता दी जायेगी। इस तरह आर्थिक और शैक्षणिक सहयोग देकर अनाथ बच्चों को समाज में पुनर्स्थापित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

- मंत्रि-परिषद ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण दिये जाने की योजना को वर्ष 2022-23 में निरंतर रखे जाने का निर्णय लिया।
  - यह ऋण किसानों को सहकारी बैंकों/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) से दिया जाता है।
  - योजना में वर्ष 2022-23 के लिये बेसरेट 10 प्रतिशत रहेगा। खरीफ 2022 सीजन के लिये देय तिथि 28 मार्च, 2023 और रबी 2022-23 सीजन के लिये देय तिथि 15 जून, 2023 रहेगी।
  - निर्धारित बेसरेट 10 प्रतिशत के अधीन खरीफ और रबी सीजन में अल्पावधि फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों के लिये 3 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा निर्धारित देय तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को 4 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रोत्साहनस्वरूप राज्य शासन द्वारा दिया जायेगा।
  - यह योजना वर्ष 2012-13 से लागू है। इसमें 3 लाख रुपए तक के अल्पावधि फसल ऋण पर राज्य शासन ब्याज अनुदान उपलब्ध कराता है।

चयनित तीन ज़िलों में 623 हेक्टेयर क्षेत्र में हुआ बाँसरोपण

चर्चा में क्यों ?

11 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के वन मंत्री डॉ. कुँवर विजय शाह ने बताया कि 'एक ज़िला-एक उत्पाद' योजना में बाँस उत्पादन के लिये चयनित तीन ज़िलों- देवास, हरदा और रीवा में पिछले वर्ष 623 हेक्टेयर क्षेत्र में बाँस का रोपण कराया जा चुका है।

प्रमुख बिंदु

- वन मंत्री ने बताया कि तीनों ज़िलों में कृषि क्षेत्र में 263 हेक्टेयर क्षेत्र तथा मनरेगा योजना में 360 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में बासरोपण का कार्य शामिल है।
- इस वित्त वर्ष के लिये इन तीनों ज़िलों में 1100 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र में मनरेगा योजना से 250 हेक्टेयर क्षेत्र और वन विभाग की योजनाओं में 750 हेक्टेयर क्षेत्र में बासरोपण का लक्ष्य दिया गया है।
- वन मंत्री डॉ. शाह ने बताया कि 'एक ज़िला-एक उत्पाद' योजना में प्रदेश के 6 ज़िले वुडन क्लस्टर में चयनित किये गए हैं। इसमें बैतूल ज़िले में सागौन, अलीराजपुर एवं उमरिया ज़िले में महुआ और देवास, हरदा तथा रीवा ज़िले को बाँस उत्पादन के लिये शामिल किया गया है।
- बाँस के लिये चयनित इन तीन ज़िलों के लिये पाँचवर्षीय रोडमेप तैयार कर उपलब्ध बाँस संसाधनों के मुताबिक लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं।
- बैतूल ज़िले को सागौन उत्पादन के लिये चयनित किया गया है। ज़िले में वुडन क्लस्टर के लिये भूमि चयन प्रक्रिया में है। वुडन क्लस्टर के लिये 71 निवेश कलाओं द्वारा तकरीबन 87 करोड़ रुपए निवेश कर इकाइयाँ चयनित की जाएंगी। इन इकाइयों से 1600 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोज़गार मिलेगा।
- इसी तरह अलीराजपुर और उमरिया ज़िले में महुआ उत्पाद के लिये हितग्राहियों का चयन प्रक्रिया में है। इन दोनों ज़िलों में वनोपज के उत्पादन के लिये बाह्य स्थलीय वृक्षारोपण कराया जाएगा।

जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया के रोगियों को होम्योपैथी दवाओं से मिला उपचार

चर्चा में क्यों ?

11 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा बताया गया कि अभी तक शासकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल द्वारा सिकल सेल एनीमिया की पहचान के लिये घर-घर जाकर स्क्रिनिंग टेस्ट किया गया, जिसमें करीब 23 हज़ार से अधिक जनजातीय व्यक्तियों का परीक्षण किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- परीक्षण के बाद 2138 जनजातीय व्यक्ति सिकल सेल रोग से पॉजिटिव पाए गए। इन रोगियों का दोबारा परीक्षण कराए जाने पर 1656 व्यक्तियों में बीमारी की पुष्टि हुई। प्रभावित व्यक्तियों को रिसर्च टीम द्वारा होम्यापैथी दवाएँ दी गईं।
- नियमित दवा देने के बाद प्रभावित व्यक्तियों को फायदा मिला है। इस बीमारी में प्रभावित व्यक्तियों में रक्त की कमी और दर्द की समस्या बनी रहती थी। दवा लेने से रोगियों को इससे छुटकारा मिला है। इन रोगियों को समय-समय पर खून चढ़ाए जाने की आवश्यकता होती थी, इससे भी उन्हें छुटकारा मिला है। इसके साथ ही इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है।
- उल्लेखनीय है कि सरकारी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 3 वर्ष पूर्व भारत सरकार की ओर से 3.75 करोड़ रुपए का एक खास प्रोजेक्ट मिला था, जिसके तहत मध्य प्रदेश की जनजातियों में इस बीमारी से ग्रसित लोगों को पहचानकर उनका इलाज किया जा रहा है।
- भारत सरकार के जनजातीय विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के आयुष विभाग के सहयोग से प्रदेश के चार ज़िलों- डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा और शहडोल में रहने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा और भारिया में सिकल सेल के उपचार के लिये विशेष परियोजना चलाई जा रही है।
- इस परियोजना में जिन रोगियों को होम्योपैथी की दवाइयाँ दी जा रही हैं, रिसर्च टीम द्वारा उनकी वर्तमान जीवन-शैली का नियमित अध्ययन भी किया जा रहा है। होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय के इस प्रोजेक्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन, एम्स, आईसीएमआर, भारतीय विज्ञान संस्थान और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल की रिसर्च कार्य में मदद ली जा रही है।
- सिकल सेल एनीमिया, एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें खून की कोशिकाओं का आकार गोल की बजाय चाँद (या हँसिए) के आकार का हो जाता है और शरीर में रक्त व ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। यह बीमारी आमतौर पर जनजातियों में होती है और इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी दवाएँ हैं, जिनसे शरीर में नया खून बनने लगे।
- ज्ञातव्य है कि मध्य प्रदेश में तीन विशेष पिछड़ी जनजाति, यथा-भारिया, बैगा एवं सहरिया निवासरत् हैं। राज्य शासन द्वारा 11 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया है, जो मंडला, बैहर (बालाघाट), डिंडोरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), शहडोल, उमरिया, ग्वालियर (दतिया ज़िला सहित), श्योपुर (भिंड, मुरैना ज़िला सहित), शिवपुरी, गुना (अशोकनगर ज़िला सहित) तथा तामिया (छिंदवाड़ा) में स्थित है। इन अभिकरणों में चिह्नांकित किये गए 2314 ग्रामों में विशेष पिछड़ी जनजाति के 5.51 लाख व्यक्ति निवास करते हैं।

मध्य प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

12 अगस्त, 2022 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रतिष्ठित केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिये चुने गए 151 पुलिसकर्मियों की सूची में मध्य प्रदेश के 10 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 के लिये घोषित 151 पुलिसकर्मियों की सूची में 28 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं।
- इस सूची में सीबीआई के 15, एनआईए के 5, महाराष्ट्र पुलिस के 11, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पुलिस के 10-10, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल पुलिस के 8-8 कर्मी और शेष अन्य राज्यों के हैं।
- इस प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में मध्य प्रदेश पुलिस के पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा, ऑफिसिएटिंग इंस्पेक्टर अवधेश सिंह तोमर, इंस्पेक्टर रवीन्द्र कुमार चावरिया, इंस्पेक्टर अमृत कुमार तिग्गा, इंस्पेक्टर सक्कूराम मरावी, महिला इंस्पेक्टर शशि विश्वकर्मा, इंस्पेक्टर संतोष कुमार पंद्रे, सब-इंस्पेक्टर उमाशंकर मुकती, महिला सब-इंस्पेक्टर सोनम रघुवंशी और सब-इंस्पेक्टर सपना राठौर शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि अपराध की जाँच में उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जाँच अधिकारियों द्वारा जाँच में इस तरह की उत्कृष्टता को मान्यता देने के उद्देश्य से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 2018 में इस पदक की स्थापना की गई थी।
- इसके तहत किसी भी अपराध की जाँच में उच्च मानकों को स्थापित करके पेशेवर रवैये को बढ़ाने, ईमानदारी, कर्त्तव्यनिष्ठा व काम से असाधारण साहस का परिचय देने वाले पुलिसकर्मियों को यह मेडल दिया जाता है।

नोट :

- 2018 में तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये पाँच पुलिस पदक शुरू किये थे। इसमें विशेष संचालन पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक, असाधारण कुशलता पदक, उत्कृष्ट एवं अति उत्कृष्ट सेवा पदक और जाँच में उत्कृष्टता पदक शामिल हैं।

आज़ादी की 'गुमनाम नायिका' सरस्वती राजामणि पर 10 साल की बेटियों ने लिखी पुस्तक

चर्चा में क्यों ?

13 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल की दो बेटियों देवयानी और शिवरंजनी के साथ पौध-रोपण कर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक 'सरस्वती राजामणि- एक भूली-बिसरी जासूस' का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- 'आज़ादी के अमृत महोत्सव'में देवयानी और शिवरंजनी अपनी पुस्तक के जरिये भारत की सबसे कम उम्र की महिला जासूस सरस्वती राजामणि से परिचय करा रही हैं। देवयानी और शिवरंजनी जुड़वाँ बहनें हैं।
- इन्होंने महज 10 साल की उम्र में आज़ाद हिन्द फौज की जासूस सरस्वती राजामणि पर सचित्र पुस्तक लिखी है। देवयानी और शिवरंजनी का कहना है 'इस वक्त जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिये, जिनके बारे में ज्यादा लिखा-पढ़ा नहीं गया है, जो हमारे गुमनाम नायक/नायिका हैं, स्वतंत्रता दिलाने में जिनका महत्त्वपूर्ण योगदान है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है।
- उल्लेखनीय है कि साल 2021 में इन बच्चियों की पहली पुस्तक 'सूर्य नमस्कार'प्रकाशित हो चुकी है, जिसे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा था।
- सरस्वती राजामणि आज़ाद हिन्द फौज की जासूस और बेहद कम उम्र की गुमनाम क्रांतिकारी थी। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बहुत प्रभावित किया था।
- सरस्वती राजामणि का जन्म बर्मा के एक संपन्न और देशभक्त परिवार में हुआ था। वे जब 16 साल की थीं, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाषण से इतनी प्रभावित हुईं कि अपने सारे गहने आज़ाद हिन्द फौज को दान कर दिये थे।
- राजामणि का हौसला और जज्बा देखकर नेताजी ने उन्हें फौज का हिस्सा बना लिया। राजामणि ने अपनी दोस्त दुर्गा के साथ मिलकर ब्रिटिश कैंप की जासूसी की और कई महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ आज़ाद हिन्द फौज को दीं। इस दौरान कई अवसरों पर उन्होंने अपनी वीरता का परिचय दिया लेकिन वह अपने ही देश में सम्मान न पा सकीं।
- देवयानी और शिवरंजनी कहती हैं कि एक युवा भारतीय को सरस्वती राजामणि का जीवन देशभक्ति, समर्पण, बहादुरी, वफादारी और बिना किसी डर के अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देता है।

इंदौर के यशवंत सागर को मिला रामसर साइट का दर्जा

चर्चा में क्यों ?

13 अगस्त, 2022 को केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पाँच राज्यों के 11 जल-स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले का यशवंत सागर भी शामिल है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब चार रामसर साइट हो गई हैं। 3 अगस्त, 2022 को इंदौर ज़िले के सिरपुर तालाब को तथा 26 जुलाई, 2022 को शिवपुरी ज़िले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सांख्य सागर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला था, जबकि भोपाल की बड़ी झील (बड़ा तालाब/भोज ताल) पहले से ही रामसर साइट घोषित है।

नोट :

- केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किये गए 11 नए रामसर साइट्स में तमिलनाडु की चार, ओडिशा की तीन, जम्मू-कश्मीर की दो और मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के एक-एक स्थल शामिल हैं। इनको मिलाकर भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के रामसर साइट्स की संख्या 75 हो गई हैं। ये आर्द्रभूमियाँ स्थल देश में 13,26,678 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हैं।
- उल्लेखनीय है कि 1971 में ईरान के रामसर में रामसर संधि पत्र पर हस्ताक्षर के अनुबंध करने वाले पक्षों में से भारत एक है। भारत ने 1 फरवरी, 1982 को इस पर हस्ताक्षर किये। विश्व में हो रहे जलवायु असंतुलन और परिवर्तन के दौर में रामसर साइट की भूमिका विश्व के पर्यावरण सुधार में अति महत्त्वपूर्ण है।
- 1982 से 2013 के दौरान, रामसर स्थलों की सूची में कुल 26 स्थलों को जोड़ा गया, हालाँकि, इस दौरान 2014 से 2022 तक, देश ने रामसर स्थलों की सूची में 49 नई आर्द्रभूमियाँ जोड़ी जा चुकी हैं।
- इस वर्ष (2022) के दौरान ही कुल 28 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर प्रमाण पत्र में अंकित स्थल की तिथि के आधार पर इस वर्ष (2022) के लिये 19 स्थल और पिछले वर्ष (2021) के लिये 14 स्थल हैं।
- तमिलनाडु में अधिकतम रामसर स्थलों की संख्या (14), इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में रामसर के 10 स्थल हैं।

डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भोपाल के कमला नेहरू कन्या स्कूल सभागार में डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अभियान पर केंद्रित पोस्टर का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- डीपीटी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिये यह टीकाकरण अभियान 31 अगस्त तक चलेगा।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश डिप्थीरिया उन्मूलन में अग्रणी राज्यों में से एक है। डीपीटी और टीडी के टीके 36 लाख किशोर-किशोरियों को लगाए जाएंगे। टीका 5 से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को लगाया जाना है। स्कूल और आँगनबाड़ी केंद्रों में नि:शुल्क टीके लगाए जाएंगे।
- स्वास्थ्य मंत्री ने जन-प्रतिनिधियों, शिक्षकों और पालकों से अभियान में शत-प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण करवाने में सहयोग करने की अपील की।
- डीपीटी (डीटीपी और DTwP भी) संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है, जो मनुष्यों को होने वाले तीन संक्रामक रोगों (डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टिटनेस) से बचाव के लिये दिये जाते हैं।
- ' D ' का मतलब डिप्थीरिया, ' T ' का मतलब टिटनेस और ' P ' का मतलब पर्टुसिस है। ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियाँ हैं। डिप्थीरिया और पर्टुसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, जबकि टिटनेस कट और घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।
- टीडी टीका टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिये दिया जाता है। यह केवल 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिये दिया जाता है। टीडी आमतौर पर हर 10 साल में बूस्टर खुराक के रूप में दिया जाता है, या गंभीर या गंदे घाव या जलने की स्थिति में 5 साल बाद दिया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होता है, जो नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। यह एक छाले के रूप में दिखाई देता है और गले में सूजन आना, गले में दर्द होना, कुछ खाने-पीने में दर्द होना, इसके लक्षण हैं। इस संक्रमण से बचने के लिये टीका बहुत ज़रूरी है।
- टिटनेस आमतौर पर पूरे शरीर में मांसपेशियों के दर्दनाक कसने का कारण बनता है। टिटनेस के कारण जबड़ा बंद हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित अपना मुँह नहीं खोल सकता और न ही निगल सकता है।
- पर्टुसिस (काली खांसी) गंभीर खांसी का कारण बनता है। इससे शिशुओं के लिये खाना, पीना या सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर्टुसिस से निमोनिया, आक्षेप, मस्तिष्क क्षति और मृत्यु हो सकती है।

नोट :

गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी-कला बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया ने किया। यह उत्सव 28 अगस्त, 2022 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया ने कहा कि माटी-कला बोर्ड के माध्यम से परंपरागत माटी शिल्प को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। माटी शिल्पी सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। इनकी शिल्प-कला को संगठित रूप से बाज़ार मुहैया कराने का कार्य बोर्ड द्वारा इस उत्सव के माध्यम से किया जा रहा है।
- इसके साथ ही हथकरघा बुनकरों द्वारा परंपरागत चरखा के माध्यम से उत्पादित सूत के बने कपड़ों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि गौहर महल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे वी.आई.पी. रोड पर शौकत महल के पास स्थित है। इस तिमंज़िले भवन का निर्माण भोपाल राज्य की तत्कालीन शासिका नवाब कुदसिया बेगम (सन् 1819-37) ने 1820 ई. में कराया था। यह वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। कुदसिया बेगम का नाम गौहर भी था, इसलिये इस महल को 'गौहर महल' के नाम से जाना जाता है।
- यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इस महल की खासियत यह है कि इसकी सजावट भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को मिलाकर की गई है। यह महल हिंदू और मुगल कला का अद्भुत संगम है।

डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों?

16 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भोपाल के कमला नेहरू कन्या स्कूल सभागार में डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अभियान पर केंद्रित पोस्टर का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- डीपीटी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिये यह टीकाकरण अभियान 31 अगस्त तक चलेगा।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश डिप्थीरिया उन्मूलन में अग्रणी राज्यों में से एक है। डीपीटी और टीडी के टीके 36 लाख किशोर-किशोरियों को लगाए जाएंगे। टीका 5 से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को लगाया जाना है। स्कूल और आँगनबाड़ी केंद्रों में नि:शुल्क टीके लगाए जाएंगे।
- स्वास्थ्य मंत्री ने जन-प्रतिनिधियों, शिक्षकों और पालकों से अभियान में शत-प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण करवाने में सहयोग करने की अपील की।
- डीपीटी (डीटीपी और DTwP भी) संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है, जो मनुष्यों को होने वाले तीन संक्रामक रोगों (डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टिटनेस) से बचाव के लिये दिये जाते हैं।
- 'D' का मतलब डिप्थीरिया, 'T' का मतलब टिटनेस और 'P' का मतलब पर्टुसिस है। ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियाँ हैं। डिप्थीरिया और पर्टुसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, जबकि टिटनेस कट और घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।
- टीडी टीका टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिये दिया जाता है। यह केवल 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिये दिया जाता है। टीडी आमतौर पर हर 10 साल में बूस्टर खुराक के रूप में दिया जाता है, या गंभीर या गंदे घाव या जलने की स्थिति में 5 साल बाद दिया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होता है, जो नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। यह एक छाले के रूप में दिखाई देता है और गले में सूजन आना, गले में दर्द होना, कुछ खाने-पीने में दर्द होना, इसके लक्षण हैं। इस संक्रमण से बचने के लिये टीका बहुत ज़रूरी है।

नोट :

- टिटनेस आमतौर पर पूरे शरीर में मांसपेशियों के दर्दनाक कसने का कारण बनता है। टिटनेस के कारण जबड़ा बंद हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित अपना मुँह नहीं खोल सकता और न ही निगल सकता है।
- पर्टुसिस (काली खांसी) गंभीर खांसी का कारण बनता है। इससे शिशुओं के लिये खाना, पीना या सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर्टुसिस से निमोनिया, आक्षेप, मस्तिष्क क्षति और मृत्यु हो सकती है।

गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी-कला बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया ने किया। यह उत्सव 28 अगस्त, 2022 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया ने कहा कि माटी-कला बोर्ड के माध्यम से परंपरागत माटी शिल्प को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। माटी शिल्पी सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। इनकी शिल्प-कला को संगठित रूप से बाज़ार मुहैया कराने का कार्य बोर्ड द्वारा इस उत्सव के माध्यम से किया जा रहा है।
- इसके साथ ही हथकरघा बुनकरों द्वारा परंपरागत चरखा के माध्यम से उत्पादित सूत के बने कपड़ों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि गौहर महल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे वी.आई.पी. रोड पर शौकत महल के पास स्थित है। इस तिमंज़िले भवन का निर्माण भोपाल राज्य की तत्कालीन शासिका नवाब कुदसिया बेगम (सन् 1819-37) ने 1820 ई. में कराया था। यह वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। कुदसिया बेगम का नाम गौहर भी था, इसलिये इस महल को 'गौहर महल' के नाम से जाना जाता है।
- यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इस महल की खासियत यह है कि इसकी सजावट भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को मिलाकर की गई है। यह महल हिंदू और मुगल कला का अद्भुत संगम है।

डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने भोपाल के कमला नेहरू कन्या स्कूल सभागार में डीपीटी/टीडी टीकाकरण अभियान के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने अभियान पर केंद्रित पोस्टर का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- डीपीटी, टिटनेस और डिप्थीरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिये यह टीकाकरण अभियान 31 अगस्त तक चलेगा।
- स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश डिप्थीरिया उन्मूलन में अग्रणी राज्यों में से एक है। डीपीटी और टीडी के टीके 36 लाख किशोर-किशोरियों को लगाए जाएंगे। टीका 5 से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष के बच्चों को लगाया जाना है। स्कूल और आँगनबाड़ी केंद्रों में नि:शुल्क टीके लगाए जाएंगे।
- स्वास्थ्य मंत्री ने जन-प्रतिनिधियों, शिक्षकों और पालकों से अभियान में शत-प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण करवाने में सहयोग करने की अपील की।
- डीपीटी (डीटीपी और DTwP भी) संयोजित टीकों की एक श्रेणी को संदर्भित करता है, जो मनुष्यों को होने वाले तीन संक्रामक रोगों (डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टिटनेस) से बचाव के लिये दिये जाते हैं।
- ' D ' का मतलब डिप्थीरिया, ' T ' का मतलब टिटनेस और ' P ' का मतलब पर्टुसिस है। ये तीनों बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियाँ हैं। डिप्थीरिया और पर्टुसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, जबकि टिटनेस कट और घावों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है।

नोट :

- टीडी टीका टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिये दिया जाता है। यह केवल 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों, किशोरों और वयस्कों के लिये दिया जाता है। टीडी आमतौर पर हर 10 साल में बूस्टर खुराक के रूप में दिया जाता है, या गंभीर या गंदे घाव या जलने की स्थिति में 5 साल बाद दिया जाता है।
- ज्ञातव्य है कि डिप्थीरिया एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण होता है, जो नाक और गले की श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। यह एक छाले के रूप में दिखाई देता है और गले में सूजन आना, गले में दर्द होना, कुछ खाने-पीने में दर्द होना, इसके लक्षण हैं। इस संक्रमण से बचने के लिये टीका बहुत ज़रूरी है।
- टिटनेस आमतौर पर पूरे शरीर में मांसपेशियों के दर्दनाक कसने का कारण बनता है। टिटनेस के कारण जबड़ा बंद हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप पीड़ित अपना मुँह नहीं खोल सकता और न ही निगल सकता है।
- पर्टुसिस (काली खांसी) गंभीर खांसी का कारण बनता है। इससे शिशुओं के लिये खाना, पीना या सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर्टुसिस से निमोनिया, आक्षेप, मस्तिष्क क्षति और मृत्यु हो सकती है।

गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

16 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं माटी-कला बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में गौहर महल में चरखा-चाक उत्सव का शुभारंभ मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया ने किया। यह उत्सव 28 अगस्त, 2022 तक चलेगा।

प्रमुख बिंदु

- अध्यक्ष जितेंद्र लिटोरिया ने कहा कि माटी-कला बोर्ड के माध्यम से परंपरागत माटी शिल्प को प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है। माटी शिल्पी सामाजिक व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। इनकी शिल्प-कला को संगठित रूप से बाज़ार मुहैया कराने का कार्य बोर्ड द्वारा इस उत्सव के माध्यम से किया जा रहा है।
- इसके साथ ही हथकरघा बुनकरों द्वारा परंपरागत चरखा के माध्यम से उत्पादित सूत के बने कपड़ों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि गौहर महल मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के बड़े तालाब के किनारे वी.आई.पी. रोड पर शौकत महल के पास स्थित है। इस तिमंज़िले भवन का निर्माण भोपाल राज्य की तत्कालीन शासिका नवाब कुदसिया बेगम (सन् 1819-37) ने 1820 ई. में कराया था। यह वास्तुकला का खूबसूरत नमूना है। कुदसिया बेगम का नाम गौहर भी था, इसलिये इस महल को 'गौहर महल' के नाम से जाना जाता है।
- यह महल भोपाल रियासत का पहला महल है। इस महल की खासियत यह है कि इसकी सजावट भारतीय और इस्लामिक वास्तुकला को मिलाकर की गई है। यह महल हिंदू और मुगल कला का अद्भुत संगम है।

GIFLIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को मिला WOW अवार्ड एशिया 2022

चर्चा में क्यों ?

21 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश पर्यटन के GIFLIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को प्रतिष्ठित WOW अवार्ड एशिया 2022 के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- GIFLIF ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल को बेस्ट कोविड सेफ्टी इवेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया।
- यह अवार्ड जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में WOW अवार्ड एशिया 2022 के 13वें संस्करण समारोह में प्रदान किया गया है।
- प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन का यह नवाचार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। यह अवार्ड हमें दर्शकों और पर्यटकों के लिये और अधिक नवाचार करने के लिये प्रेरित करेगा।
- प्रमुख सचिव ने बताया कि कोविड-19 के समय में यह भारत का पहला ड्राइव-इन म्यूजिक फेस्टिवल था, जिसमें कोविड-19 के सभी मानदंडों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था।

नोट :

- एमपी टूरिज्म, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी और व्हाइट वॉल्स मीडिया द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखते हुए GIFLIF संस्था के सहयोग से यह फेस्टिवल आयोजित किया गया।
- कॉमेडी और म्यूजिक फेस्ट, द ग्रेट इंडियन फिल्म एंड लिटरेचर फेस्टिवल (GIFLIF) 26 और 27 मार्च, 2022 को एमपीटी डीडीएक्स ड्राइव-इन-सिनेमा में हुआ था। देश के सुप्रसिद्ध कलाकार और म्यूजिक बैंड बॉम्बे बंदूक, बल्ली मारन, चार हज़ारी और अग्नि ने फेस्टिवल में अपनी प्रस्तुतियाँ दी थीं।
- गौरतलब है कि WOW अवार्ड एक्सपेरिमेंटल मार्केटिंग, MICE, LIVE एंटरटेनमेंट और वेडिंग इंडस्ट्री में एशिया का सबसे बड़ा बिज़नेस और रिकॉग्निशन प्लेटफार्म है।

12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

22 अगस्त, 2022 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के प्रो. जगदीशचंद्र बसु सभागार में दीप प्रज्वलित कर 12वें नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मैपकास्ट द्वारा आयोजित इस फिल्म फेस्टिवल में 71 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल 26 अगस्त तक चलेगा। उद्घाटन सत्र को छोड़कर अन्य दिनों में फिल्म का प्रदर्शन रवींद्र भवन में होगा।
- मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने फेस्टिवल का उद्घाटन करने के बाद घोषणा करते हुए कहा कि भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने तथा विज्ञान को जन-जन तक ले जाने के लिये आगामी एक वर्ष में विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन मध्य प्रदेश के संभागीय मुख्यालयों में उत्सव के रूप में किया जाएगा।
- विज्ञान फिल्मोत्सव का शुभारंभ महान भारतीय वैज्ञानिक पी.सी. रे पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के साथ हुआ। विज्ञान भारती और संस्कृति मंत्रालय द्वारा बनाई गई यह फिल्म आधुनिक रसायन शास्त्र के पितृपुरुष प्रफुल्ल चंद्र रे, स्वाधीनता के पहले शिक्षा जगत, रोज़गार, गरीबी उन्मूलन और भारत में रासायनिक उद्योग के विकास में असाधारण योगदान पर केंद्रित थी।
- ओशन (महासागर) पर प्रदर्शित दूसरी डॉक्यूमेंट्री में महासागरों की अद्भुत जैव विविधता पर मँडराते खतरों और उसे बचाने पर ज़ोर दिया गया है।
- समारोह के दौरान होने वाली विभिन्न स्पर्धाओं के लिये करीब 16 लाख रुपए कीमत के पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में वितरित किये जाएंगे।
- गौरतलब है कि राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव में निम्नांकित प्रतिस्पर्धी श्रेणियों में डाक्यूमेंट्री फिल्में, शॉर्ट फिल्म, एनिमेशन फिल्म, डाक्यू ड्रामा, साइंस फिक्शन आमंत्रित किये जाते हैं एवं लगभग 16 लाख रुपए के नकद पुरस्कार इंटरफेस, फ्यूजन श्रेणी (स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं), आउट ऑफ बॉक्स श्रेणी-कालेज विद्यार्थियों, इंद्रधनुष श्रेणी (स्कूल विद्यार्थियों) आदि में भारत सरकार की ओर से दिये जाते हैं।

ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश के सभी 528 शासकीय महाविद्यालय और 16 शासकीय विश्वविद्यालय भारत सरकार के एनआईसी के ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से सीधे जुड़ेंगे।

प्रमुख बिंदु

- उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव की उपस्थिति में मंत्रालय में एनआईसी और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में एमओयू पर हस्ताक्षर किये।

नोट :

- उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से उच्च शिक्षा में अध्ययनरत् प्रदेश के 16 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। इस सॉफ्टवेयर से विद्यार्थियों को दुर्लभ पुस्तकें भी डिजिटल फॉर्मेट में पढ़ने के लिये उपलब्ध हो सकेंगी। इससे अकादमिक गुणवत्ता में सुधार होगा।
- गौरतलब है कि वर्तमान में देश के 28 हज़ार शिक्षण संस्थान ई-ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। यह मोबाइल पर भी उपलब्ध है। विद्यार्थी ऑनलाइन पंजीयन कर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
- महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में उपलब्ध संसाधनों को इस पर अपलोड किया जा सकता है, जिससे अन्य महाविद्यालय, विश्वविद्यालय उनका लाभ ले सकें।
- एनआईसी के अधिकारियों ने बताया कि सॉफ्टवेयर के उपयोग को लेकर महाविद्यालय की लाइब्रेरी में पदस्थ स्टाफ और प्राध्यापकों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

एशिया का पहला कागज़ कारखाना फिर से शुरू

चर्चा में क्यों ?

23 अगस्त, 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ने बुरहानपुर स्थित एशिया की पहली कागज़ मिल नेपा लिमिटेड का लोकार्पण किया। इसे सात साल बाद पुन: शुरू किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि 2015 में रिनोवेशन के लिये इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। केंद्र सरकार से मिले करीब 469 करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज से मिल का नवीनीकरण किया गया है।
- पहले मिल की उत्पादन क्षमता 88 हज़ार मीट्रिक टन प्रतिवर्ष थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक कर दिया गया है। यहाँ आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं।
- यहाँ दो प्रकार का कागज़ तैयार होगा। पहला न्यूज़ प्रिंट, जो 44-45 जीएसएम का होगा। यह वेस्टेज कागज से लुगदी बनाकर तैयार किया जाएगा तो वहीं दूसरा राइटिंग प्रिंटिंग पेपर होगा।
- उल्लेखनीय है कि नेपा लिमिटेड की शुरुआत 26 जनवरी, 1947 को नायर प्रेस सिंडिकेट लिमिटेड ने एक निजी उद्यम के रूप में की थी। न्यूज़ प्रिंट उत्पादन के लिये 'द नेशनल न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड'के नाम गठित यह कंपनी, 1981 तक भारत में एकमात्र न्यूज़ प्रिंट मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट थी।
- अक्तूबर 1949 में कंपनी के प्रबंधन को मध्य प्रांत और बरार (वर्तमान में मध्य प्रदेश) की तत्कालीन राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत कर लिया गया। मिल में कमर्शियल उत्पादन शुरू होने के साथ ही, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 26 अप्रैल, 1959 को इसे देश को समर्पित किया। 21 फरवरी, 1989 को कंपनी का नाम बदल कर नेपा लिमिटेड कर दिया गया।

गांधी मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी हिन्दी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में 2022-23 के सत्र से एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई हिन्दी माध्यम से आरंभ की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समाचार-पत्र समूह द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एजुकेशन समिट-2022 में निवास कार्यालय से वर्चुअली सम्मिलित होकर यह जानकारी दी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जुलाई 2022 से प्रदेश के 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बी.टेक पाठ्यक्रमों तथा 6 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मातृभाषा हिन्दी में पढ़ाई की व्यवस्था की गई है।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर शिक्षण के लिये 5-सी (क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलेबरेशन, क्यूरोसिटी और कम्युनिकेशन) को महत्त्वपूर्ण बताया है। प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इन सभी पर काम हो रहा है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में अध्ययन और अध्यापन पर विशेष ज़ोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति सच्चे अर्थों में ज्ञान, कौशल और संस्कार का त्रिवेणी संगम है। नई शिक्षा नीति में ज्ञान के महत्त्व को 5 रूपों में समाहित किया गया है।
- इसमें भारतीय ज्ञान और दर्शन परंपरा को पढ़ाई के माध्यम से नई पीढ़ियों को सौंपना, कॉन्सेप्ट की समझ आधारित शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा को नंबर गेम एवं गला काट प्रतियोगिता से मुक्त कर ग्रेडिंग तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित करना शामिल है। साथ ही शोध और अनुसंधान को बढ़ावा तथा शिक्षा को बहुआयामी बनाना भी नई शिक्षा नीति का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा को कौशल विकास और रोज़गार से जोड़ने के लिये प्रभावी कार्य जारी है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल शिक्षण के लिये ग्लोबल स्किल पार्क बनाया जा रहा है। प्रदेश में 10 संभागीय आई.टी.आई. को आदर्श आई.टी.आई. के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रदेश में नई स्टार्टअप नीति लागू कर दी गई है।
- स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में महापुरुषों की जीवनी, अमर शहीदों की गाथाएँ और नैतिक शिक्षा का समावेश किया गया है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश में कुल अध्ययनरत विद्यार्थियों का तीन प्रतिशत नेशनल कैडेट कोर में भाग लें।
- मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन'योजना और 'मुख्यमंत्री छात्रगृह' योजना की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में शुरू हुए सीएम राइज स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात करेंगे।

मध्य प्रदेश के दो शिक्षक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित

चर्चा में क्यों ?

25 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिये चयनित देश के विभिन्न राज्यों के 46 शिक्षकों के नाम की अंतिम सूची जारी की। इसमें मध्य प्रदेश के दो शिक्षकों के नाम भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु चयनित शिक्षक-शिक्षिकाओं को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 5 सितंबर, 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। पुरस्कार के तौर पर शिक्षक-शिक्षिकाओं को 50 हज़ार रुपए की राशि और सिल्वर मेडल दिया जाएगा।
- शिक्षक दिवस पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिये जाने वाले राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित मध्य प्रदेश के दो शिक्षकों में रायसेन ज़िले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सालेगढ़ के शिक्षक नीरज सक्सेना और शाजापुर ज़िले के राजकीय उत्कृष्टता उच्च माध्यमिक विद्यालय के लेक्चरर ओम प्रकाश पाटीदार शामिल हैं।
- गौरतलब है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रतिवर्ष 5 सितंबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।
- पुरस्कारों के लिये शिक्षकों का चयन ऑनलाइन तीनस्तरीय चयन प्रक्रिया के ज़रिये पारदर्शी तरीके से किया जाता है।
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है।

'मांडू'बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन अवार्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

24 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित 19वें वार्षिक आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स समारोह में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल 'मांडू' को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिये आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी की उपस्थिति में आउटलुक ट्रैवलर अवाड्र्स दिया गया। मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के प्रबंध संचालक एस. विश्वनाथन ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष पुरस्कारों का 19वाँ वर्ष है। वहीं इस वर्ष आउटलुक ग्रुप के शिखर सम्मेलन का विषय 'यात्रा का तीसरा युग'निर्धारित है।
- इस वर्ष पुरस्कार का निर्णय एक शोध एजेंसी द्वारा यात्रा सर्वेक्षण तथा जूरी सदस्यों द्वारा प्रतिक्रियाओं की जाँच के आधार पर किया गया।

ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

27 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) में चारदिवसीय 'ग्वालियर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव'का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- उद्भव सांस्कृतिक एवं खेल संस्थान द्वारा अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में अपने नवगठित प्रकल्प 'उद्भव साहित्यिक मंच'के तत्वावधान में केंद्रीय अकादमी स्कूल एवं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सहयोग से 'प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ग्वालियर साहित्य उत्सव'का आयोजन 27 से 30 अगस्त, 2022 तक किया जा रहा है।
- ग्वालियर चंबल अंचल के साहित्य साधकों की साधना को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाने के उद्देश्य से इस साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- इस साहित्य उत्सव में अंचल के साहित्यकारों का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकारों के साथ साक्षात्कार होगा।

मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर का शिलान्यास

चर्चा में क्यों ?

27 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के अमरदास हॉल में आयोजित रोज़गार दिवस कार्यक्रम में मध्य भारत के पहले टॉय क्लस्टर 'इंदौर इंटरनेशनल टॉय क्लस्टर'का वर्चुअल शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिये एक ई-लर्निंग मॉड्यूल भी लॉन्च किया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 42 क्लस्टर स्वीकृत किये गए हैं, जिनमें से 84 करोड़ रुपए की लागत से बने इस टॉय क्लस्टर का शुभारंभ इंदौर में किया गया। मध्य भारत के इस पहले टॉय क्लस्टर में 20 लघु इकाइयाँ स्थापित होंगी तथा दो हज़ार से अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे।
- इस क्लस्टर के प्रथम चरण में 80 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। इसी तरह विभिन्न क्लस्टरों के माध्यम से प्रदेश में न केवल निवेश बढ़ेगा, बल्कि रोज़गार के अवसर कई गुना अधिक तेज़ी से प्रदान किये जा सकेंगे।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में हर माह प्रदेश भर में रोज़गार दिवस मनाने और ढाई लाख बेरोज़गारों को रोज़गार से जोड़ने की घोषणा की।
- मुख्यमंत्री ने स्वरोज़गार योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक एवं ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किये। स्वरोज़गार के लिये 75 हज़ार से अधिक हितग्राहियों को 466 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री द्वारा चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रमाण-पत्र भी वितरित किये गए।

नोट :

- गौरतलब है कि 12 जनवरी, 2022 को मध्य प्रदेश में प्रथम रोज़गार दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के 5 लाख से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं के तहत रोज़गार प्रदान किया गया। 31 मार्च, 2022 तक विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर लगभग 13 लाख हितग्राहियों को 7 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया।

इंदौर में बना प्रदेश का पहला जी.आई.एस. अति उच्च-दाब सब-स्टेशन

चर्चा में क्यों ?

29 अगस्त, 2022 को मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक इंजीनियर सुनील तिवारी ने बताया कि मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए महानगर इंदौर के पारेषण नेटवर्क को मज़बूती और विश्वसनीयता प्रदान करने के लिये प्रदेश के पहले जी.आई.एस. (गैस इंसूलिटेड स्विच गियर सब-स्टेशन) को ऊर्जीकृत किया है।

प्रमुख बिंदु

- प्रबंध संचालक सुनील तिवारी ने बताया कि इंदौर में विद्युत की बढ़ती मांग को देखते हुए मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को इंदौर शहर में अतिरिक्त सब-स्टेशन के निर्माण की ज़रूरत महसूस हुई। इंदौर जैसी घनी आबादी में परंपरागत सब-स्टेशन के निर्माण के लिये पर्याप्त भूमि की उपलब्धता नहीं होने के कारण मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर में जी.आई.एस. सब-स्टेशन (गैस इंसूलिटेड स्विच गियर सब-स्टेशन) तैयार करने का निर्णय लिया।
- करीब 36 करोड़ 50 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित इंदौर के महालक्ष्मी नगर में 50 एम.वी.ए. क्षमता के साथ इस सब-स्टेशन को ऊर्जीकृत किया गया है।
- मध्य प्रदेश का यह पहला जी.आई.एस. अति उच्च-दाब सब-स्टेशन है, जो मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के पारेषण नेटवर्क में जुड़ा है।
- इस सब-स्टेशन के प्रारंभ हो जाने से इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में विद्युत पारेषण व्यवस्था को मज़बूती मिलने के साथ इंदौर को अति उच्च-दाब सब-स्टेशन का एक और विकल्प उपलब्ध हो गया है।
- जी.आई.एस. सब-स्टेशन के निर्माण में परंपरागत एयर इंसूलेटेड सबस्टेशनों के मुकाबले कम भूमि की ज़रूरत पड़ती है। इस तकनीक से सब-स्टेशन के निर्माण का बजट परंपरागत सब-स्टेशन की तुलना में लगभग ढाई गुना अधिक रहता है, पर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने इंदौर की ज़रूरत को देखते हुए इस निर्माण की मंज़ूरी दी। गैस इंसूलेटेड चैंबर में रहने के कारण इन सबस्टेशनों के उपकरणों में कम खराबी आती है। इन्हें 'मेंटेनेंस फ्री' सब-स्टेशन भी कहा जाता है।

मध्य प्रदेश मंत्रि-परिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

30 अगस्त, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन के अनुसमर्थन के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद ने राज्य के प्रत्येक नागरिक को स्वस्थ जीवन शैली एवं निरोग जीवन जीने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश योग आयोग के गठन का अनुसमर्थन किया।
  - आयोग अपनी गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से करेगा। मध्य प्रदेश योग आयोग का प्रशासकीय विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होगा।
  - आयोग में राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में कार्यरत एवं अति विशिष्ट योगदान देने वाले अशासकीय व्यक्ति अध्यक्ष रहेंगे।

नोट :

- महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष (पदेन) योग आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में रहेंगे। राज्य शासन द्वारा मनोनीत योग के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले 5 व्यक्ति अशासकीय सदस्य के रूप में रहेंगे। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक पदेन सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
- योग आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट में किया जाएगा। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष, चिकित्सा शिक्षा, सामाजिक न्याय, खेल एवं युवा कल्याण, जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव के प्रतिनिधि शासकीय सदस्य होंगे।
- अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

- मंत्रि-परिषद ने विशेष प्रकरण मानते हुए बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को थॉमस कप में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर 10 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप देने का निर्णय लिया।
- मंत्रि-परिषद द्वारा खनिज साधन विभाग में खनिज राजस्व बकाया की वसूली के लिये 'समाधान योजना' मंज़ूर की गई है।
  - योजना में वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक खनिज राजस्व बकाया पर देय ब्याज पूर्णत: माफ किया गया है।
  - वर्ष 2010-11 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि में 5 लाख रुपए तक बकाया राशि पर देय ब्याज पूर्णत: माफ एवं 5 लाख रुपए से अधिक बकाया राशि पर देय ब्याज पर 18 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया। इसके अनुसार छूट देने के बाद मूल बकाया राशि 60 करोड़ 7 लाख रुपए के विरुद्ध ब्याज सहित राशि 66 करोड़ 48 लाख रुपए की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।
  - समाधान योजना 31 अक्टूबर, 2022 तक लागू रहेगी। यदि खनिज बकाया के विरुद्ध न्यायालयीन वाद प्रचालित हैं, तब इस योजना में राशि जमा होने पर वाद वापस लिया जा सकेगा।
  - योजना के लागू होने से वर्ष 1960-61 से वर्ष 2019-20 तक की लंबित बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित हो सकेगी।
- मंत्रि-परिषद ने मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2022 को पुनर्स्थापित करने के प्रारूप को अनुमोदित किया।
  - संशोधन विधेयक, 2022 के अनुसार अध्यादेश से पूर्व में प्रेस्टीज विश्वविद्यालय इंदौर, टाइम्स विश्वविद्यालय भोपाल, डॉ. प्रीति ग्लोबल विश्वविद्यालय शिवपुरी एवं एल.एन.सी.टी. विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर को स्थापित किया गया है।
  - इसके साथ ही अन्य 3 निजी विश्वविद्यालय अमलतास विश्वविद्यालय देवास, आर्यावर्त विश्वविद्यालय सीहोर एवं विक्रांत विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना के लिये विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित किया गया।
- उल्लेखनीय है कि संस्कृत भाषा तथा उसके साहित्य के अध्यापन क्षेत्र में अनुसंधान और व्यापक अध्ययन को बढ़ावा देने के प्रयोजन से स्कूल स्तर पर संस्कृत शिक्षा को विनियमित करने के लिये उससे संशक्त एवं आनुषांगिक अन्य विषयों के लिये एक अधिनियम के माध्यम से महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की 2008 में स्थापना हुई। इसका मुख्यालय एमपी नगर भोपाल में है।

नोट :